International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद मध्य एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका

[1] Mukesh Kumar , [2] Dr. Dinesh Mandot, [3] Dr. Nand Kishor Somani
[1] Research Scholar, (Pol. Sc.),
[2 & 3] Research Guide ,Bhagwant University Ajmer, Rajasthan, India
Email Id: mukeshkumardeva5563@gmail.com

Pol.Sc.- Res. Paper-Accepted Dt. 15 Aug. 2024 **Pub** : **Dt.**14Sept.2024

सारांश

इस शोध प्रपत्र में मैंने विषय ''अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद मध्य एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका'' का यथासभंव वर्णन किया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के हटने के कारण मध्य एशिया में सत्ता का शून्य हो गया है, जिसने चीन, रूस, भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों को इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। चीन ने मध्य एशिया के बुनियादी ढांचे में कुल 100 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है और वर्ष 2000 से 2020 के बीच इस क्षेत्र का वाणिज्य 1.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 50 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। दूसरी ओर, रूस ने इस क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्र में कुल 10 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 5,000 से अधिक सैनिकों की सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। इसके अतिरिक्त, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के साथ अपने वाणिज्य का काफी बढ़ाया है और भारत ने मध्य एशिया के ऊर्जा क्षेत्र में कुल एक बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, भारत ने अफगानिस्तान को कुल दो बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। यह काफी संभावना है कि क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा की गतिशीलता इन आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा हितों से प्रभावित होगी क्योंकि यह क्षेत्र निरंतर परिवर्तन से गुजर रहा है। तालिबान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास तथा क्षेत्र के राष्ट्रों द्वारा वाणिज्य, जल विवाद तथा उग्रवाद उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषया पर मध्य मार्ग खोजने के प्रयास, दोनों ही क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, पश्चिमी देशों को इन प्रयासों में बाधा डालने के बजाय व्यापक सुरक्षा सहयोग तथा आर्थिक एकीकरण के लिए क्षेत्रीय पहलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

शब्दकुंजी–सत्ता, मध्य एशिया, ऊर्जा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जल विवाद, उग्रवाद राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण आदि।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्रस्तावना

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के तुरंत बाद क्षेत्र के आर्थिक और सुरक्षा परिदृ"य को स्थापित करने में मध्य एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान सहित क्षेत्र के देश अब आथिक और सुरक्षा स्थिरता के लिए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये घटनाएँ उसी समय हो रही हैं जब तालिबान विदेशी संगठनों के साथ संबंध बनाने के प्रयास कर रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र के प्रत्येक देश तालिबान से निपटने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाते हैं, वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि सरकार के साथ संपर्क की खुली रेखाएँ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालाँकि, उनकी भागीदारी इस तथ्य के कारण सीमित है कि वे सरकार को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और क्योंकि पश्चिम ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। अफगानिस्तान को तालिबान द्वारा ''यूरेशियन महाद्वीपों'' को जोड़ने वाले पुल के रूप में माना जाता है, और क्षेत्र के देश उन मुद्दों पर एक आम जमीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। व्यापार को बढ़ावा देना, जल विवादों का समाधान करना और अंतरराष्ट्रीय उग्रवाद को खत्म करना कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है। क्षेत्र में शांति की गारंटी देने के तरीके के रूप में, पश्चिमी देशों को इन प्रयासों में बाधा डालने के बजाय व्यापक सुरक्षा सहयोग और आथिक एकीकरण के लिए क्षेत्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि क्षेत्र में शांति बनी रहे।

शोध के उद्देश्य

इस शोध के उद्देश्यों निम्नलिखित है–

- अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद मध्य एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों (जैसे चीन, रूस, भारत और अन्य) की भू–राजनीतिक रणनीतियों का विश्लेषण करना।
- मध्य एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के निवेश और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के आर्थिक प्रभावों का आकलन करना।
- क्षेत्रीय शक्तियों और मध्य एशियाई राज्यों के बीच सुरक्षा गतिशीलता और सहयोग ढाँचे की जाँच करना।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अफगानिस्तान में अमेरिकी भागीदारी और उसकी वापसी का संक्षिप्त अवलोकन

अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी अक्टूबर 2001 में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के जवाब में शुरू हुई, जो अल–कायदा द्वारा आयोजित किए गए थे, जो अफगानिस्तान में तालिबान शासन द्वारा आश्रय प्राप्त एक आतंकवादी समूह है। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के रूप में जाने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप के प्राथमिक उद्देश्य अल–कायदा के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए तालिबान को सत्ता से हटाना और अफगानिस्तान को आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकना था।

शुरू में, हस्तक्षेप तालिबान को प्रमुख शहरों से खदेड़ने और अल–कायदा के संचालन को बाधित करने में सफल रहा। अमेरिका ने अफगान विपक्षी ताकतों के साथ मिलकर एक नई सरकार की स्थापना की, जिसके साथ दिसंबर 2001 में हामिद करजई अंतरिम अफगान राष्ट्रपति बने।

बाद के वर्षों में, अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लोकतंत्रीकरण, बुनियादी ढाँचे के विकास और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार सहित राष्ट्र निर्माण प्रयासों के माध्यम से अफगानिस्तान को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी रहीं, जिनमें तालिबान विद्रोह का फिर से उभरना, शासन संबंधी मुद्दे, भ्रष्टाचार और सुस्त अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

2009 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तालिबान के पुनरुत्थान का मुकाबला करने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाकर और सुरक्षा जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करके अमेरिकी रणनीति में बदलाव किया। अफगान सैन्य और पुलिस क्षमताओं के निर्माण के प्रयासों के बावजूद, सुरक्षा स्थिति अनिश्चित बनी रही, जिसमें निरंतर हिंसा और अस्थिरता देखी गई।

फरवरी 2020 में, अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आतंकवाद को रोकने और अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तालिबान की प्रतिबद्धताओं के बदले में अमेरिकी सैनिकों की चरणबद्ध वापसी की रूपरेखा तैयार की गई थी। वापसो मई 2021 में शुरू हुई और अगस्त 2021 तक पूरी हो गई, जो तालिबान के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तेजी से क्षेत्रीय लाभ और अफगान राजधानी काबुल पर अंततः कब्जा करने के साथ मेल खाती है।

अमेरिका की वापसी ने दो दशकों से अधिक समय तक चले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध का अंत किया, जिसमें महत्वपूर्ण मानवीय और वित्तीय लागतें थीं। इसने अफगानिस्तान की स्थिरता, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के निहितार्थों के भविष्य के बारे में चिंताएँ पैदा कीं। अफगान सरकार का तेजी से पतन और काबुल हवाई अड्डे पर अराजक निकासी प्रयासों ने वापसी प्रक्रिया की जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित किया।

क्षेत्रीय शक्तियों के हित

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद मध्य एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के हित बहुआयामी हैं और विभिन्न प्रेरणाओं से प्रेरित हैं। चीन, रूस, भारत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के हितों को दशाने के लिए निम्नलिखित आकड दिए गए हैं–

चीन

मध्य एशिया के साथ चीन का व्यापार 2000 में $1.4 बिलियन से बढ़कर 2020 में $ 50 बिलियन से अधिक हो गया है। (स्रोतः चीनी सीमा शुल्क ब्यूरो)।

चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के हिस्से के रूप में सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं सहित मध्य एशिया के बुनियादी ढांचे में $100 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। (स्रोतः चीन का राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग)।

मध्य एशिया से चीन का ऊर्जा आयात 2010 में उसके कुल ऊर्जा आयात के 10 प्रति"ात से बढ़कर 2020 में 20 प्रति"ात से अधिक हो गया है। (स्रोतः चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो)।

रूस

रूस का मध्य एशिया के साथ व्यापार 2000 में 5.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 20 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। (स्रोतः रूसी संघीय सीमा शुल्क सेवा)।

रूस ने मध्य एशिया के ऊर्जा क्षेत्र में 10 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में तेल और गैस क्षेत्रों का विकास शामिल है। (स्रोतः रूसी ऊर्जा मंत्रालय)।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मध्य एशिया में रूस की सैन्य उपस्थिति बढ़ गई है, इस क्षेत्र में 5,000 से अधिक सैनिक तैनात ह, जिनमें किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। (स्रोतः रूसी रक्षा मंत्रालय)।

भारत

भारत का मध्य एशिया के साथ व्यापार 2000 में 100 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। (स्रोतः भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

भारत ने मध्य एशिया के ऊर्जा क्षेत्र में 1 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में तेल और गैस क्षेत्रों का विकास शामिल है। (स्रोतः भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)।

भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों सहित अफगानिस्तान को 2 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। (स्रोतः भारतीय विदेश मंत्रालय)।

अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ

मध्य एशिया के साथ तुर्की का व्यापार 2000 में 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। (स्रोतः तुर्की सांख्यिकी संस्थान)।

मध्य एशिया के साथ ईरान का व्यापार 2000 में 500 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 5 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। (स्रोतः ईरानी सीमा शुल्क प्रशासन)।

मध्य एशिया के साथ पाकिस्तान का व्यापार 2000 में 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 2 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। (स्रोतः पाकिस्तानी सांख्यिकी ब्यूरो)।

क्षेत्रीय संगठन और बहुपक्षीय दृष्टिकोण

अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद मध्य एशिया के भू–राजनीतिक और आर्थिक परिदृ”य को आकार देने में क्षेत्रीय संगठन और बहुपक्षीय दृष्टिकोण तेजी से कार्यरत हा गए। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) जैसे प्रमुख संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शंघाई सहयोग संगठन

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

1. गठन और उद्देश्य—चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढाना है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए, जिससे इसका भू–राजनीतिक प्रभाव बढ़ा।

2. सुरक्षा सहयोग—अमेरिका की वापसी के बाद, शंघाई सहयोग संगठन ने आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। शंघाई सहयोग सगठनका क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी ढांचा खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त आतंकवाद–रोधी अभ्यासों में सदस्य देशों के प्रयासों का समन्वय करता है। अफगानिस्तान से मध्य एशिया में चरमपंथी गतिविधियों के संभावित फैलाव को देखते हुए ये पहल महत्वपूर्ण हैं।

3. आर्थिक एकीकरण—शंघाई सहयोग संगठन चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों में कनेक्टिविटी और व्यापार बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। शंघाई सहयोग संगठन बिजनेस काउंसिल और इंटरबैंक कंसोर्टियम आर्थिक सहयोग, निवेश और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाते हैं।

4. राजनयिक जुड़ाव—शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के बीच संवाद और कूटनीतिक जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय दृष्टिकाण को बढ़ावा देता है, कूटनीतिक चौनलों के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देता है और द्विपक्षीय तनाव को कम करता है।

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन

1. गठन और उद्देश्य—सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन 1992 की सामूहिक सुरक्षा संधि के उत्तराधिकारी के रूप में 2002 में स्थापित किया गया था, जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। संगठन आपसी रक्षा, सैन्य सहयोग और सामूहिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।

2. सैन्य सहयोग—अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के जवाब में, सामूहिक सरक्षा संधि संगठन ने मध्य एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। संयुक्त सैन्य

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अभ्यास, जैसे ''रूबेज'' (सीमांत), सदस्य देशों के बीच अंतर–संचालन और तत्परता को बढ़ाते हैं। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन सुरक्षा संकटों को दूर करने के लिए तेजी से तैनाती बला के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है।

3. सीमा सुरक्षा–सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन अपने सदस्य देशों की सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से अफगानिस्तान से सटे देशों की। इसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और शरणार्थिया और अवैध सामानों के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए रसद और तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है।

4. संकट प्रतिक्रिया–सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संकट प्रतिक्रिया तंत्र सुरक्षा खतरों की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस क्षमता का प्रदशन 2022 में किया गया था जब नागरिक अशांति की अवधि के दौरान स्थिति को स्थिर करने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन बलों को कजाकिस्तान में तैनात किया गया था।

3. अन्य बहुपक्षीय पहल

1. आर्थिक सहयोग संगठन–अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों सहित दस सदस्य देशों से मिलकर बना आर्थिक सहयोग संगठनआर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। अमेरिका की वापसी के बाद, क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा सहयोग और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने में आर्थिक सहयोग संगठन की भूमिका ने महत्व प्राप्त कर लिया है।

2. अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन–अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढावा देना है। यह पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक साथ लाता है जो अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों को लाभ पहुँचा सकते हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निश्कर्श

निष्कर्ष के तौर पर, अफगानिस्तान से अमेरिको सैनिकों की वापसी ने मध्य एशिया में एक शक्ति शून्यता पैदा कर दी है, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों को इस क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। चीन, रूस, भारत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य एशिया में महत्वपूर्ण आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा हित है, जैसा कि शोध प्रपत्र में वर्णन किए गए डेटा से स्पष्ट है। ये हित क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा की गतिशीलता को आकार देने की संभावना रखते हैं। इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने, जल विवादों को सुलझाने और अंतरराष्ट्रीय चरमपंथ को खत्म करने जैसी चुनौतियाँ हैं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, पश्चिमी देशों को व्यापक सुरक्षा सहयोग और आर्थिक एकीकरण के लिए क्षेत्रीय प्रयासों को बाधित करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्षेत्रीय शक्तियों और तालिबान के बीच एक साझा आधार बनाने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः एक अधिक स्थिर और सुरक्षित मध्य एशिया का निर्माण होगा।

सदंर्भ ग्रन्थ सुची

1. रियरडन–एंडरसन, जे. (2020)– मध्य एशिया में महान खेलः रूस, चीन और प्रभाव के लिए संघर्ष। रूटलेज।
2. कुसेरा, जे. (2020)– नया महान खेलः चीन, रूस और मध्य एशिया के लिए संघर्ष। आई.बी. टॉरिस।
3. जोशी, मनोज– ''भारत की उभरती मध्य एशिया नीतिः सामरिक, सुरक्षा और आर्थिक आयाम।'' रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) अंक संक्षिप्त, संख्या 285 (2019)।
4. गनीव, ओलिमजोन–''चीन की मध्य एशिया नीति का आर्थिक आयामः सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट पहल।'' जर्नल ऑफ यूरेशियन स्टडीज 7, संख्या 2 (2016): 126–138।
5. स्टार, एस.एफ. (2015)– खोया ज्ञानोदयः अरब विजय से लेकर तामेरलेन तक मध्य एशिया का स्वर्ण युग। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. अहरारी, एम.ई. (2017)– मध्य एशिया में नया महान खेलः भूराजनीति, ऊर्जा और सुरक्षा। मिशिगन यूनिवर्सिटी प्रेस।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 09 Sep- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

7. अरोड़ा, वी. ''मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के संबंधः रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक परिप्रेक्ष्य।'' रणनीतिक विश्लेषण 36, संख्या 6 (2012)रू 896–909।
8. हसन, मोहम्मद महमूदुल– ''अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत के हित।'' आईडीएसए मोनोग्राफ श्रृंखला संख्या 54 (2006)।